भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1815** जिसका उत्तर

मंगलवार, 4 अगस्त, 2026 (13 श्रावण, 1948, (शक)) को दिया जाना है

अलंग-सोसिया जहाज पुनर्चक्रण यार्ड

1815 # श्री राजेश परमानंद शुक्ला:

क्या **पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अलंग-सोसिया जहाज पुनर्चक्रण यार्ड में पुनर्चक्रित (रीसायकल) जहाजों की कुल संख्या तथा संभाले गए कुल टन भार का ब्यौरा क्या है और जहाज पुनर्चक्रण की मात्रा में आई गिरावट के क्या कारण हैं;

(ख) अस्पताल सुविधाओं, आवासीय कॉलोनियों और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं सहित श्रमिकों के लिए विकसित स्वास्थ्य और सामाजिक अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंदी के दौरान जहाज पुनर्चक्रण उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार/गुजरात मैरिटाइम बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): वर्ष 2025 में भारत दुनिया का अग्रणी पोत पुनर्चक्रण राष्ट्र बन गया है। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (यूएनसीटीएडी) रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक पोत पुनर्चक्रण में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2024 के 30.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 35.4% हो गई है। भारत में पोत पुनर्चक्रण वर्ष 2024 के 1.86 मिलियन जीटी से काफी बढ़कर वर्ष 2025 में 2.99 मिलियन जीटी हो गया है, अर्थात् इसमें 60% की वृद्धि हुई है। गुजरात में 1982-83 में

स्थापित अलंग-सोसिया पोत पुनर्चक्रण यार्ड, भारत की पोत पुनर्चक्रण गतिविधियों का 98% हिस्सा संभाल रहा है। इस यार्ड में वर्तमान में 128 प्रचालनरत प्लॉट हैं जिनकी पुनर्चक्रण क्षमता 4.5 मिलियन लाइट डिस्पलेसमेंट टनेज (एलडीटी) प्रति वर्ष है। अपनी स्थापना के बाद से, अलंग यार्ड में 71 मिलियन एलडीटी से अधिक के 8,900 से अधिक पोतों का पुनर्चक्रण किया जा चुका है।

वैश्विक पोत पुनर्चक्रण की मात्रा वर्ष 2019 के 12.05 मिलियन ग्रॉस टन (जीटी) से लगभग 30% घटकर वर्ष 2025 में 8.48 मिलियन जीटी रह गई है, जिसका श्रेय कोविड-19 महामारी के बाद से उच्च चार्टर दरों, नए जलयानों की उच्च कीमतों और लाल सागर संकट जैसी भू-राजनीतिक स्थितियों जैसे कारकों के कारण जलयानों के लंबे समय तक उपयोग किए जाने को दिया जा सकता है। व्यापक वैश्विक मंदी के रुझान के बीच भले ही पूर्ण पुनर्चक्रण मात्रा में गिरावट आई है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य के संबंध में भारत की सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी ने अधिक लचीलापन दिखाया है।

(ख): अलंग-सोसिया पोत पुनर्चक्रण यार्ड के कार्मिकों हेतु एक व्यापक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है। मार्च, 2019 में एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया गया था और जनवरी 2025 में इसे 35 बिस्तरों वाले लेवल III ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रचालित यह अस्पताल, गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू), एमआरआई, सीटी स्कैन, बर्न यूनिट और ऑपरेशन थिएटर सहित उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। 43 स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की टीम से युक्त यह अस्पताल निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है और जून 2026 तक 4.79 लाख से अधिक रोगियों का उपचार कर चुका है। इसके अतिरिक्त, गुजरात के अलंग में एक अन्य प्राथमिक अस्पताल के रखरखाव और प्रचालन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

कर्मचारी कल्याण के लिए, गुजरात समुद्री बोर्ड (जीएमबी) ने 1,008 व्यक्तियों के आवास के लिए आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त एक आवासीय कॉलोनी विकसित की है।

(ग): भारतीय पोत पुनर्चक्रण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 'पोत भंजन (शिपब्रेकिंग) क्रेडिट नोट योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, जब किसी एचकेसी अनुपालन प्राप्त भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्ड में पोत का पुनर्चक्रण किया जाता है, तो

पोत स्वामियों को पुनर्चक्रित पोत के स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर एक क्रेडिट नोट दिया जाता है। इस क्रेडिट नोट का उपयोग किसी भारतीय शिपयार्ड में बनाए गए नए पोत के संविदा मूल्य के 5% तक के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिससे घरेलू पोत पुनर्चक्रण और पोत निर्माण, दोनों को बढ़ावा मिलता है।

अन्य उपायों में मार्च, 2035 तक पुनर्चक्रण के लिए आयातित जलयानों पर शून्य आयात शुल्क और विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान जीएमबी द्वारा प्लॉट अनुमति धारकों को दी गई 145.23 करोड़ रुपये की वित्तीय छूट शामिल है।

पोत पुनर्चक्रण इकोसिस्टम को सुदृढ़ के लिए, लौह अयस्क स्क्रैप विकास कोष (एफएसडीएफ) के तहत भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्डों को एचकेसी अनुपालक बनने में मदद करने के लिए 53.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने यूरोपीय संघ की स्वीकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं की सूची में पात्र भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्डों को शामिल करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए यूरोपीय प्राधिकारियों से संपर्क किया है।

*****